International Journal of Advanced Research in Engineering Technology & Science
ISSN: 2349-2819
Email: editor@ijarets.org Volume-10, Issue-7 July – 2023 www.ijarets.org

वर्तमान संदर्भ में सामाजिक न्याय

Dr. Babu Lal Meena
Professor in Pol Science
S P C Govt College Ajmer

सार

सामाजिक न्याय उस निष्पक्षता से संबंधित है जिसके साथ सामूहिक जीवन से उत्पन्न होने वाले सामान और बोझ को समाज के सदस्यों के बीच साझा किया जाता है। सामाजिक न्याय की समस्या से जो मुख्य प्रश्न उठते हैं, वे सामाजिक वस्तुओं के वितरण में शामिल विभिन्न आयामों से संबंधित हैं: वितरित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामाजिक वस्तुएं क्या हैं? उचित वितरण को रेखांकित करने वाले सिद्धांत क्या हैं? कौन से एजेंट और प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि सामाजिक वस्तुओं का वितरण निष्पक्ष हो?

मुख्य शब्द: *संदर्भ, सामाजिक न्याय*

परिचय

न्याय की अवधारणा के कई आयाम हैं। यह दूसरों के साथ व्यवहार में तर्कसंगत व्यक्ति के प्रमुख गुणों में से एक है; यह कानूनी व्यवस्था का आधार है; और यह वह महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से समाज के कार्य करने के विभिन्न तरीकों पर निर्णय लिया जाता है। इन विभिन्न आयामों और अनुप्रयोग के क्षेत्रों के नीचे, अर्थ की एक सामान्य एकता मौजूद है, यदि न्याय को केवल "प्रत्येक को उनका हक देना" के रूप में परिभाषित किया गया है। उस परिभाषा के अनुसार, सामाजिक न्याय उस प्रकार का न्याय है जो तब प्राप्त किया जाता है जब सामाजिक व्यवस्थाएं हर किसी के लिए अपना हक प्राप्त करना संभव बनाती हैं। हालाँकि सामान्य तौर पर न्याय के कई आयाम हैं, सामाजिक न्याय का संबंध विशेष रूप से समुदाय के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन से उत्पन्न संसाधनों के उचित वितरण से है। सामाजिक न्याय के बारे में प्रश्न इसलिए समाज में न्यायपूर्ण वितरण के संगठन के बारे में प्रश्न हैं, यह "मामलों की उचित स्थिति" को दर्शाता है ... जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल वही लाभ और बोझ मिलते हैं जो उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं और परिस्थितियों के आधार पर उसके कारण होते हैं। " (मिलर 1975, 20), या रॉल के प्रसिद्ध कथन में: "सामाजिक सहयोग से उत्पन्न होने वाले लाभ और बोझ का पर्याप्त पुनर्विभाजन" (रॉल्स 1999, 4)। भले ही न्याय पर दार्शनिक चिंतन ने शुरू से ही इसमें निहित वितरणात्मक आयाम की पहचान की है (अरस्तू 2000), सामाजिक लाभों और बोझों के उचित वितरण के मुद्दे को केवल बाजार समाजों के उदय के साथ एक समस्या के रूप में पहचाना गया था, जिसमें एक ओर जनसंख्या के बड़े से बड़े वर्गों को बुनियादी व्यक्तिगत अधिकार प्रदान किए गए, वहीं दूसरी ओर कार्य संगठन के पूंजीवादी स्वरूप और उससे जुड़ी सामाजिक संरचना ने आर्थिक और सामाजिक असमानता के ऐसे चरम रूप पैदा कर दिए कि उन पर औचित्य का दबाव बढ़ गया। तेजी से अनुचित समझा जा रहा है। संक्षेप में, यह दावा करना अनुचित नहीं है कि सामाजिक न्याय का प्रश्न "सामाजिक प्रश्न" के उदय के साथ ही उत्पन्न हुआ।

सामाजिक न्याय के उद्देश्य

मनुष्य विभिन्न प्रकार की बौद्धिक, शारीरिक और भावनात्मक क्षमताओं के कारण "प्राकृतिक" प्रकार से भिन्न होते हैं। असमानता के इस प्रारंभिक "प्राकृतिक" रूप में, सामाजिक जीवन व्यक्तियों के बीच एक दूसरे प्रकार

का भेदभाव जोड़ता है। मनुष्य को न केवल जीवित रहने के लिए, बल्कि फलने-फूलने और अपनी जीवन परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है। सामाजिक सहयोग सभी प्रकार के सामान और "बुराइयों" का वितरण लाता है। रॉल्स के अनुसार, सामाजिक जीवन द्वारा उत्पादित वस्तुओं का वर्णन करने के लिए एक प्रचलित शब्द "सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं" है। ये वे वस्तुएं हैं जिन पर समाज का सीधा नियंत्रण होता है, स्वास्थ्य और बुद्धि जैसी "प्राकृतिक" निधियों के विपरीत, जिन पर सामाजिक जीवन केवल प्रभाव डालता है (रॉल्स 1999, 54)। सूची में "अधिकार, स्वतंत्रता, धन, आय, अवसर और आत्म-सम्मान के आधार पर सामाजिक मान्यता के रूप" शामिल हैं। इनमें सामाजिक जीवन में निहित "बुराइयों" को भी जोड़ा जा सकता है, जैसे अपमानजनक या गंदा काम। हालाँकि, सामाजिक सहयोग द्वारा उत्पादित "शेयर" समान रूप से वितरित नहीं किए जाते हैं। श्रम का विभाजन अनिवार्य रूप से शेयरों का असमान वितरण लाता है: रोजगार और बेरोजगारी, आय और धन की असमानता के रूप में उत्पादन के लाभों के साथ-साथ कम या ज्यादा मूल्यवान व्यवसायों और प्रकारों तक पहुंच में। गतिविधि। श्रम विभाजन से जुड़े भौतिक और प्रतीकात्मक पुरस्कारों से सीधे संबंध में कई प्रकार के सामान पूरे समाज में वितरित किए जाते हैं, जैसे शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य संसाधन, सांस्कृतिक संसाधनों तक पहुंच, इत्यादि। पूरे समाज में धन, स्थिति, जीवन की संभावनाओं और अवसरों के इस वितरण से जुड़ी, सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली, विशेष रूप से जाति और लिंग के आसपास, लाभ और बोझ के वितरण का एक निश्चित पैटर्न तैयार करती है जो व्यक्तियों के समग्र जीवन की संभावनाओं और स्वयं के अवसरों को परिभाषित करती है। विकास। आधुनिक, बाजार समाजों की एक विशिष्ट पहेली के कारण, जीवन अवसरों के इस वितरण के संबंध में सामाजिक न्याय का प्रश्न उठता है। एक ओर, निष्पक्षता के कुछ सिद्धांत पहले से ही श्रम और समाज के सांस्कृतिक पैटर्न के संगठन में अंतर्निहित रूप से काम कर रहे हैं, इसमें शामिल मौजूदा संस्थानों और प्रक्रियाओं को बाधित और सह-निर्धारित कर रहे हैं। और फिर भी, क्योंकि लाभ और बोझ का वितरण असमान है, उन सिद्धांतों की पूर्ण प्राप्ति के बीच का अंतर देखने में बहुत स्पष्ट है, जो असमानता, गरीबी और सभी प्रकार के भेदभाव (नस्लवाद, लिंगवाद) की घटनाओं में व्यक्त होता है, जो पूर्णता की मांग करता है। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्पष्ट करना।

समाज द्वारा व्यक्तियों को "क्या देय" है?

आधुनिक समाजों में सामाजिक न्याय की मांग से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का पहला सेट उन मानदंडों पर केंद्रित है जिनके द्वारा सामाजिक वस्तुओं को उचित रूप से वितरित किया जाना है। तीन सिद्धांत उन अधिकारों के आधार पर संभावित पुनर्वितरण का मार्गदर्शन करते हैं जो व्यक्ति और समूह समाज पर उनके कारण कुछ के रूप में दावा कर सकते हैं: अधिकारों के रूप में समझे जाने वाले अधिकार; जैसा कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित है; या, किसी ऐसी चीज़ के रूप में जिसके वे हकदार हैं। चर्चा सबसे पहले उन सिद्धांतों में से प्रत्येक की उचित परिभाषा और व्याख्या पर चर्चा करती है, कि क्या तीनों में से किसी को किसी अन्य सिद्धांत में घटाया जा सकता है, और उन्हें एक-दूसरे के साथ कैसे जोड़ा जाना चाहिए। सभी समकालीन सिद्धांत अधिकारों को सामाजिक न्याय का अपरिहार्य आधार बनाते हैं, वास्तव में, कई खातों में, सामाजिक न्याय अधिकारों के दावे का पर्याय है। समकालीन राजनीतिक विचार में एक विशेष रूप से मजबूत विवरण भौतिक अभिव्यक्ति और नैतिक स्वायत्तता की मजबूती के रूप में अधिकारों की शास्त्रीय कांतियन परिभाषा का अनुसरण करता है, स्वतंत्रता के लिए बाद की क्षमता के आधार पर किसी व्यक्ति की स्थिति 'अपने आप में अंत' के रूप में होती है, लेकिन इस स्वायत्तता की विशेषता इस प्रकार है: 'स्व-स्वामित्व', और व्युत्पत्ति से स्वामित्व बनता है, दूसरे शब्दों में संपत्ति का अधिकार, किसी व्यक्ति की स्वायत्तता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति और विस्तार। अधिकारों

के ऐसे मामले में, कोई भी पुनर्वितरण तंत्र स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है और इसलिए यह एक मौलिक अन्याय है (नोज़िक 1974)। नतीजतन, सामाजिक रूप से उत्पन्न असमानता का तथ्य पुनर्वितरण को उचित ठहराने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अधिकारों और सामाजिक न्याय के बीच संबंध पर जोर देने से न्याय और पुनर्वितरण के बीच संबंध को अस्वीकार किया जा सकता है। इसके विपरीत, समतावादी खाते जो पुनर्वितरण तंत्र के तरीकों और औचित्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह मानते हैं कि मौलिक अधिकारों को "सुव्यवस्थित समाज" में सुरक्षित और स्थापित किया जाना है और सामाजिक धन और सामाजिक रूप से उत्पादित अवसरों पर व्यक्तिगत अधिकारों को सामान के रूप में अवधारणाबद्ध करते हैं, जिस पर वंचित व्यक्तियों को लाभ मिलता है। उचित दावे हैं. उस मामले में, सामाजिक न्याय और अधिकारों के बीच संबंध फिर से अंतर्निहित है, लेकिन बहुत अलग अर्थ में और बहुत अलग राजनीतिक परिणामों के साथ।

सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं के उचित वितरण को व्यवस्थित करने का दूसरा सिद्धांत यह है कि बाद वाले को उन लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए जो इसके लायक हैं, जिन्होंने इसे अर्जित किया है: उन लोगों के लिए अधिक आय जिन्होंने कड़ी मेहनत की है या अधिक उत्पादन किया है, या सामाजिक रूप से मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन किया है; उन लोगों के लिए उच्च सामाजिक स्थिति जिन्होंने सामाजिक रूप से मूल्यवान गतिविधियाँ हासिल की हैं; शैक्षिक अवसर, उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश, उन लोगों के लिए जिन्होंने अध्ययन के पहले स्तर पर अपनी योग्यता साबित की है, इत्यादि। यहां मुख्य समस्या उन मानदंडों के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके द्वारा सामाजिक उपलब्धियों को मापा जाना है। एक बुनियादी विकल्प, किए गए सामाजिक योगदान के मूल्य के विपरीत, खर्च किए गए प्रयास के प्रतिफल के बीच निहित है। इस पर चर्चा उतनी ही कठिन है जितनी अंतर्ज्ञान व्यापक है, कि सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण हद तक उन लोगों को उनका हक देना शामिल है जो इसके हकदार हैं। योग्यता के सिद्धांतों को विस्तृत करने का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण तरीका अवसर की समानता का सिद्धांत है। अवसर की समानता सामाजिक न्याय की समकालीन समझ के मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। सिद्धांत इस विचार पर विस्तार से बताता है कि, उन स्थितियों में जहां लिंग, नस्ल या किसी अन्य अनुचित मानदंड के आधार पर भेदभाव को हटाकर अवसरों को बराबर किया गया है, जो लोग अपने निर्णयों और कार्यों के माध्यम से अधिक मात्रा में सामाजिक लाभ प्राप्त करते हैं, वे इसके हकदार हैं। . वास्तव में, उन्हें अपने स्वयं के कार्यों से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित करना एक अन्याय होगा, और यह वास्तव में समाज की एक ऐसी स्थिति के लिए प्रयास करना न्याय के मुख्य दांवों में से एक है जिसमें भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की जीवन योजना से जुड़ी सामाजिक वस्तुओं को सुरक्षित करने का प्रयास करें। हालाँकि, यह केंद्रीय सिद्धांत समकालीन राजनीतिक दर्शन की एक केंद्रीय आपत्ति के विरुद्ध है: अर्थात्, यह तथ्य कि प्राकृतिक असमानताएँ नैतिक दृष्टि से उतनी ही कम प्रासंगिक हैं जितनी कि सामाजिक रूप से उत्पन्न असमानताएँ। तदनुसार, यह मान लेना वास्तव में गलत है कि बड़ी उपलब्धियाँ, चाहे उन्हें जिस भी तरह से परिभाषित की गई हों, उन्हें अधिक सामाजिक पुरस्कार आकर्षित करना चाहिए, यदि वे उन क्षमताओं पर आधारित हैं जो विरासत में मिली हैं। समकालीन राजनीतिक दर्शन में अधिकांश सिद्धांत उन योजनाओं के आविष्कार के इर्द-गिर्द घूमते रहे हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक शेयरों के नैतिक रूप से पर्याप्त पुनर्वितरण को संबोधित करना है, जब सामाजिक और प्राकृतिक असमानताओं को पूर्ण सामाजिक न्याय में बाधाओं के रूप में पहचाना गया है। अंत में, आवश्यकता की अवधारणा सामाजिक न्याय के एक सिद्धांत के रूप में विवादित है क्योंकि यह दावों की एक अघुलनशील श्रृंखला को नामित करती प्रतीत होती है। तीन मूल सिद्धांतों में से, संभवतः यह वह है जिसकी सबसे अधिक आलोचना की गई है। कई लेखकों ने दावा किया है कि इसे अन्य सिद्धांत (बैरी 1965) में घटाया जा सकता है। कई लोगों ने इसके बारे में

पर्याप्त सैद्धांतिक चिंताएं उठाई हैं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि "सच्ची" और "झूठी" जरूरतों के बीच, मात्र इच्छाओं, इच्छाओं और आंतरिक जरूरतों के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त मानदंडों के साथ आना मुश्किल लगता है, और क्योंकि जरूरतों का संदर्भ खराब हो सकता है एक निर्धारित मानव स्वभाव जैसी किसी चीज़ के प्रति एक भोली-भाली अपील। और फिर भी, उन सभी सैद्धांतिक संदेहों के लिए, आवश्यकता का सिद्धांत न्याय के दावों को स्थापित करने वाला एक अपरिवर्तनीय सिद्धांत बना हुआ है और इस तरह कई सिद्धांतकारों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है (रेनॉल्ट 2004)। यह आधुनिक समाजों में व्यक्तियों पर क्या बकाया है, इसके बारे में एक मौलिक अंतर्ज्ञान से मेल खाता है, यह सिद्धांत मार्क्स द्वारा पहले से ही सरल शब्दों में प्रतिपादित किया गया है, जिसमें पहले से ही योगदान के साथ जरूरतों को स्पष्ट किया गया है: "प्रत्येक से उनकी क्षमताओं के अनुसार, प्रत्येक को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार " (मार्क्स 2008)। मार्क्स का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य भी तीन सिद्धांतों के बीच निर्णय लेने का मुद्दा उठाता है। रॉल के न्याय सिद्धांत के प्रमुख पहलुओं में से एक सटीक रूप से ऐसा करने के लिए एक विधि की पेशकश करना है। आवश्यकताओं को संस्थागत व्यवस्था की मुख्य मानक शर्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। हालाँकि, वे अन्य सिद्धांतों, पहले सिद्धांत में निहित अधिकारों और स्वतंत्रता और दूसरे में स्थापित अवसर की समानता से बाधित हैं। तथ्य यह है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस हद तक उचित ठहराया जाता है कि वे सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को लाभ पहुंचाती हैं, जिससे प्रदर्शन और योग्यता को इस तरह से पुरस्कृत किया जा सकता है जो उन्हें अधिकारों और जरूरतों के अनुकूल बनाता है। रॉल्स के विपरीत, अन्य सिद्धांतकारों ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि वास्तविक सामाजिक-राजनीतिक जीवन तीन सिद्धांतों (मिलर 1999) के बीच अस्थिर तनाव में निहित है।

सामाजिक न्याय के एजेंट और प्रक्रियाएँ

मुद्दों का दूसरा समूह उन एजेंटों और प्रक्रियाओं से संबंधित है जिन्हें पुनर्वितरण को प्रभावित करना है। सामाजिक न्याय के तीन मुख्य एजेंट हैं: राज्य और उसकी संस्थाएँ; बाज़ार, श्रम और वस्तु बाज़ार; और समाज स्वयं सामाजिक बंधन द्वारा अपनाए गए स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए नैतिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के संदर्भ में विचार करता है। उन एजेंटों में से प्रत्येक को दिया गया महत्व सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकारों, रेगिस्तानों और जरूरतों को किस तरह से व्यक्त किया गया है। उदारवादी मॉडल में, जिसमें अधिकार अन्य सिद्धांतों से ऊपर हैं, एक केंद्रीय विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सरकार के हस्तक्षेप पर संदेह है। इसके विरुद्ध, कार्य प्रयासों के कुशल समन्वय और सभी के प्रयासों के उत्पादों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने वाले तंत्र के रूप में बाजार पर भरोसा किया जाता है। इस मॉडल में, बाजार तंत्र के परिणामस्वरूप जीवन की संभावनाओं का वितरण सबसे कुशल और निष्पक्ष है। इन तंत्रों में हस्तक्षेप न केवल अक्षमताओं का परिचय देता है, बल्कि अन्यायपूर्ण भी है क्योंकि यह स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। इसलिए राज्य की भूमिका केवल संस्थागत, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत करने वाली कानूनी प्रक्रियाओं और बाजार तंत्र को बढ़ावा देने की है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक संपर्क में आते हैं। अपने पूर्ण व्यक्तिवाद के बावजूद, ऐसा मॉडल सामाजिक न्याय को सभी स्वतंत्र नागरिकों के संयुक्त प्रयासों के उत्पाद के रूप में समुदाय से जुड़े एक गुण के रूप में संदर्भित करने के लिए जारी रह सकता है। स्पष्ट रूप से यह मॉडल केवल एक सैद्धांतिक निर्माण नहीं है। 70 के दशक के उत्तरार्ध से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के नवउदारवादी पुनर्गठन के खाके के रूप में, इसके विभिन्न संस्करण स्थापित नीति सोच का केंद्र बने हुए हैं। हालाँकि, इसके विरुद्ध, राजनीतिक सिद्धांतकारों का एक बड़ा हिस्सा, और वास्तव में समकालीन समाजों का बड़ा हिस्सा मानता है कि लाभ और बोझ का प्राकृतिक वितरण व्यक्तिगत बंदोबस्ती से लेकर शक्ति और/या विशेषाधिकार की अयोग्य प्रारंभिक

स्थिति के कारण अंतर्निहित असमानताओं से ग्रस्त है। विरासत में मिली संपत्ति और सामाजिक स्थिति। समतावादी दृष्टिकोण बाजार तंत्र को कम करने और पुनर्निर्देशित करने के लिए सिद्धांतों को तैयार करके उचित वितरण की इन विकृतियों को दूर करना चाहते हैं ताकि वे उचित परिणाम दे सकें। उचित पद्धतिगत दृष्टिकोण से संबंधित सैद्धांतिक मतभेदों से परे, समतावादी दृष्टिकोण का सामान्य लक्ष्य सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अवसर की समानता सुनिश्चित करना है। बाजार को अभी भी आपूर्ति और मांग के कुशल समन्वय के साथ सौंपा गया है, लेकिन सरकारी एजेंसियों को वितरण में कई कमियों को दूर करने के लिए कराधान, सब्सिडी, नियमों में बदलाव, विशेष रूप से संपत्ति कानूनों में बदलाव के माध्यम से बाजार तंत्र में हस्तक्षेप के कई रूप दिए गए हैं। बाज़ारों द्वारा प्रभावित सामाजिक शेयर। बाज़ार की विशिष्ट कमियाँ पहले से ही आर्थिक स्तर पर शुरू हो जाती हैं, जैसे कि प्रमुख बाज़ार स्थितियों और एकाधिकार का अपरिहार्य गठन, बेहिसाब नकारात्मक सामाजिक लागत और बाह्यताएँ, बुनियादी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए बाज़ार की कीमतों की अक्षमता, या बाज़ार की असमर्थता। आय का ऐसा वितरण करें जिससे हर कोई रहने योग्य जीवन स्तर तक पहुंच सके (रॉल्स 1999, 243)। अवसर की समानता के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसरों, प्रतिष्ठा के पदों के साथ-साथ शिक्षा और संस्कृति तक समान पहुंच प्राप्त हो। संक्षेप में, सामाजिक न्याय के लिए समतावादी दृष्टिकोण सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं के असमानतावादी प्रभावों को ठीक करने के लिए डिज़ाइन किए गए मजबूत संस्थागत और संस्थागत तंत्र तैयार करके लाभ और बोझ के उचित पुनर्वितरण को मजबूत करना चाहते हैं। निःसंदेह सामाजिक समन्वय के अपूरणीय तंत्र के रूप में बाजारों पर निर्भरता स्वयं आलोचना का विषय हो सकती है, खासकर यदि विश्लेषण मौजूदा पूंजीवादी बाजारों के परिप्रेक्ष्य से किया जाता है। इस दृष्टिकोण से, सामाजिक अन्याय का मुख्य स्रोत निश्चित रूप से उस तरीके में पाया जाता है जिसमें बाजार तंत्र सामाजिक वर्चस्व को सुरक्षित और मजबूत करता है।

अंत में, कई दृष्टिकोणों ने संस्थागत डिजाइन और सरकारी एजेंसियों के हस्तक्षेप के अलावा अन्य प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। "महत्वपूर्ण सिद्धांत" के व्यापक क्षेत्र में, "समाज की बुनियादी संरचना" को रेखांकित करने वाले प्रमुख सामाजिक मानदंडों और मूल्यों की व्याख्याओं की प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर दिया गया है। इनमें से कुछ दृष्टिकोणों में, उदाहरण के लिए स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मान्यता के अलावा, पुनर्वितरण की समस्या को समाज के सामने आने वाली मुख्य नियामक समस्याओं में से एक के रूप में निपटाया जाता है (फ्रेजर 2009)। वैकल्पिक रूप से समाज के सांस्कृतिक आधार की संरचना करने वाली विषमताओं को सामाजिक अन्याय की जड़ के रूप में देखा जाता है, और इसलिए पुनर्वितरण से पहले सामाजिक न्याय के दावों की पहली वस्तु के रूप में देखा जाता है (यंग 2011)। हालाँकि, इन वैकल्पिक दृष्टिकोणों में, सामाजिक न्याय के एजेंट राज्य संस्थाएँ और बाज़ार बने रहते हैं, लेकिन केवल इस हद तक कि सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के नाम पर छेड़े गए सामाजिक आंदोलनों के परिणामस्वरूप उनका मुकाबला किया जाता है और उन्हें बदल दिया जाता है (होनेथ 1994)।

निष्कर्ष

सामाजिक आंदोलनों पर यह ध्यान सामाजिक न्याय की सीमाओं का मुद्दा भी उठाता है। सभी स्तरों पर वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों में तेजी से विकास ने आधुनिक राजनीतिक दर्शन की एक प्रमुख धारणा को समस्याग्रस्त बना दिया है, अर्थात्, मुख्य प्रासंगिक ढांचे के रूप में राष्ट्र-राज्य का संदर्भ।

संदर्भ

[1] अरस्तू. 2000. निकोमैचियन एथिक्स। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। बैरी, ब्रायन. 1965. राजनीतिक तर्क. लंडन। फ़्रेज़र, नैन्सी। 2009.

[2] न्याय का तराजू. वैश्विक दुनिया में राजनीतिक स्थान की पुनर्कल्पना। न्यूयार्क, कोलंबिया विश्वविद्यालय प्रेस। होनेथ, एक्सल। 1995.

[3] मान्यता के लिए संघर्ष. सामाजिक संघर्ष का नैतिक व्याकरण। लंदन: पॉलिटी प्रेस. मार्क्स, कार्ल. 2008. गोथा कार्यक्रम की आलोचना।

[4] रॉकविल: वाइल्डसाइड प्रेस। मिलर, डेविड. 1976. सामाजिक न्याय, संशोधित संस्करण। ऑक्सफ़ोर्ड: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

[5] मिलर, डेविड. 1999. सामाजिक न्याय के सिद्धांत। कैम्ब्रिज, एमए: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। नोज़िक, रॉबर्ट। 1974. अराजकता, राज्य और स्वप्नलोक। न्यूयॉर्क: बेसिक बुक्स।

[6] रॉल्स, जॉन. 1999. न्याय का एक सिद्धांत। कैम्ब्रिज, एमए: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। रॉल्स, जॉन. 1993. राजनीतिक उदारवाद। न्यूयार्क, कोलंबिया विश्वविद्यालय प्रेस। रेनॉल्ट, इमैनुएल। 2004.

[7] अन्याय का अनुभव. पेरिस: ला डेकोवर्टे। यंग, आइरिस मैरियन। न्याय और अंतर की राजनीति. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस.

[8] एकरमैन, ब्रूस। 1980. उदार राज्य में सामाजिक न्याय। न्यूयॉर्क: येल यूनिवर्सिटी प्रेस.

[9] कार्वर, एन.टी. 1915. सामाजिक न्याय में निबंध। कैम्ब्रिज, मास: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

[10] एल्स्टर, जॉन. 1992. स्थानीय न्याय: संस्थाएँ दुर्लभ वस्तुओं और आवश्यक बोझों का आवंटन कैसे करती हैं।

[11] किम्लिका, विल। 2002. समसामयिक राजनीतिक दर्शन। ऑक्सफ़ोर्ड: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

[12] वाल्ज़र, माइकल. 1983. न्याय के क्षेत्र: बहुलवाद और समानता की रक्षा। ऑक्सफोर्ड: मार्टिन रॉबर्टसन।

[13] विलोबी, डब्ल्यू.डब्ल्यू. 1900. सामाजिक न्याय. न्यूयॉर्क: मैकमिलन.